वर्ष : 9 अंक : 1, मई : 2011, सहयोग राशी 2 रुपये RNI-DELHIN/2003/9926

युवा भारत समाचार

सेवा में,

संपादक मंडल: शशी सोनवणे, राजीव राय, इक्बाल गाजी.
संपादकीय कार्यालय : 167ए/जी.एच-२, पश्चिम विहार, नई दिल्ली - 63
ए-101, पूनम आस्था पूनम गार्डन, तिरुपती नगर-२, विरार (प), जि. ठाणे, महाराष्ट्र - 401303. फोन 9209225862.

समन्वयक की कलम से

क्या फुकुशिमा से अब तो हम सीखेंगे ?

हाल ही में आए भयंकर भूकंप और त्सूनामी से जपान का जनजीवन पूरी तरह से तहस नहस हो गया. ११ मार्च को हुए ९.० रिश्टर स्केल के इस भयंकर भूकंप और उर उसकी वजह से आए त्सूनामी के कारण हजारो लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए. जपान भूकंप प्रवण क्षेत्र में होने के कारण वहां पर भूकंप के संदर्भ में नागरीकों को पूरी जानकारी दी जाती है और आपातकालीन परिस्थिती की उपाय योजना के बारे में सभी को ट्रेनिंग भी दी जाती हैं. फिर भी इतने बडे कुदरती संकट का सामना करने के लिए जपानी यंत्रणा पर्याप्त नहीं थी. इस त्रासदी से जान माल का भारी नुकसान हुआ है. आर्थिक मंदी से झूझती जपान की अर्थ व्यवस्था अधिक गहरे संकट में फस गई हैं. उस से भी गहरा संकट परमाणू विकिरण के रुप में झेलना पड रहां हैं. २० मिटर से अधिक उंची समुद्री लहरों ने जपान के सेन्दाई प्रांत के फुकुशिमा डाइची परमाणू विद्युत केन्द्र को तबाह कर दिया. पिछले दो महिने से जपान इस परमाणू संकट से झूझ रहा हैं. फुकुशिमा डाइची का परमाणू संयंत्र पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया हैं और उससे परमाणू विकिरण तेजी से फैल रहा हैं. यहा तक की १५० मील दूरी पर टोकियो शहर के पानी, दूध, मछली और सब्जीयों में रेडीयेशन पाया गया हैं. इस परमाणू विकिरण के परिणाम अगली कई सदी तक हम सब को झेलने पडेंगे. हिरोशिमा नागासाकी की याद दिलाने वाले इस संकट ने परमाणू ऊर्जा के सुरक्षितता को लेकर कई सवाल खडे कर दिये हैं. ऐसी विपरीत स्थिती में भी मनमहोन सिंह सरकार परमाणू ऊर्जा कार्यक्रम को लागू करने में लगी है. उसके लिए अपनेही नागरीकों पर

पृ **4** पर

अन्ना 'लाईव'

भ्रष्टाचार जैसे गंभीर विषय पर अन्ना हजारे दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठ गए. इस उपोषण ने पुरे देशभर के मध्यम वर्ग को जागृत कर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक व्यापक लहर पैदा की. आम जनता के भ्रष्टाचार के प्रति घृणा, गुस्से को अन्ना हजारे ने आवाज दिया. हमारे लिए भ्रष्टाचार नया मुद्दा नहीं. लेकिन पिछले कुछ वर्षो में हजारो करोड़ रुपयो के घोटाले एक के पिछे एक इस तरह से बाहर आए हैं कि उन घोटालोने मनमोहन सिंह - सोनिया गांधी की सरकार ही नहीं पुरी व्यवस्था पर सवाल खडा हो गया था. ऐसी स्थिती में उसके खिलाफ गांधी टोपी पहनकर उसे प्रामाणिकता से विरोध करे तो उसे समर्थन मिलना स्वाभाविक हैं. लेकिन भ्रष्टाचार जैसे गंभीर समस्या को लोकपाल विधेयक में समेट लेना, मिडीया खास करके टेलिविजन मिडीया का उसे बढचढकर अन्ना को दुसरा गांधी घोषित करते हुए अन्य अरब देशों की तरह 'पिकॉक' (भारत का राष्ट्रीय पक्षी - मोर) क्रांती करार कर देना हस्यास्पद ही नहीं बल्कि इस देश के आम जनता के जीने - मरने के संघर्षो पर उडाया गया बेहुदा मजाक हैं.

जंतर मंतर में आकर अभिनेता टॉम अल्टर ने बाईबल का दाखिला देते हुए कहां की जो पापी न हो वहीं पहला पत्थर मारे. लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी लढे उनका स्वागतही होना चाहिए. सवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ की लढाई का नहीं. सवाल मर्ज की व्याख्या करने का हैं और उसकी दवाई का. भ्रष्टाचार के विरोध में केवल लोकपाल ही अक्सीर इलाज है यह जो चित्र मिडीया द्वारा किया जा रहा हैं वह गलत हैं. जितने घोटाले सामने आए हैं उन

पृ **2** पर

युवा भारत राष्ट्रीय शिविर

5-6-7 जून, 2011, भागलपूर, बिहार

युवा भारत संगठन की स्थापना के १० वर्ष पुरे हो गए. बीसवीं सदी के अंतिम दशकों में देश और दुनिया की राजनीतिक स्थिती का आकलन करते हुए यु.भा. जैसे संगठन की प्रासंगिकता को समझकर बना. पिछले १० वर्षो में यु.भा. ने साम्राज्यवाद विरोधी लढाई में कई महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किए साथ ही साथ कई सारे सांगठनिक उतार चढाव भी देखे. इन अनुभवों का लेखा-जोखा रखते हुए वर्तमान परिस्थिती का ठोस विश्लेषण और नई संभावनाओं को तलाशने के लिए यु. भा. साथीयों का वैचारीक शिविर भागलपूर, बिहार में आयोजित किया हैं. शिविर संबंधी जानकारी के लिए

संपर्क करे - राजीव राय : 9430869781 प्रदिप राय : 9830224319 कौशिक भारत : 9804800724

पृ १ से

भ्रष्टाचारीयों के खिलाफ सख्त कारवाई करने के लिए कानून में पर्याप्त गुंजाईश हैं. लेकिन जहां जिसे भ्रष्टाचारीयो पर नजर रखने के लिए बिठाया हो वही भ्रष्ट हो, उसकी नियुक्ती में ही भ्रष्टाचार हो तो और एक कानून लाकर क्या होगा? यह सवाल आम जनता के मन में हैं. सरकारी लोकपाल विधेयक बेशक सरकारी बाबू, मंत्रीयों के भ्रष्टाचार को बचाने की भूमिका से बनाया गया हैं. लेकिन जो सिविल सोसायटीवालो ने जो जन लोकपाल विधेयक बनाया हैं वह तो मर्ज से दवाई भयंकर ऐसा हैं. भ्रष्टाचार के खिलाफ लढने की बात करना आसान हैं लेकिन उसे व्याख्यित करना बहुत कठीण हैं. भ्रष्टाचार सापेक्ष संकल्पना हैं. हर वर्ग जाती के अनुरुप भ्रष्टाचार की व्याख्या और उसकी व्यापकता बदलती हैं. मोमबत्ती जलानेवाले ज्यादातर लोग छठा वेतन आयोग की तनखा लेनेवाले हैं, नवउदारमतवादी नीतियो से लाभ लेनेवाले हैं. इसलिए उनका आंदोलन भी 'टॅक्स पेयर' होने के अहंकार से ग्रस्त हैं होने के कारण केवल लोकपाल की नियुक्ती में समेट जाता हैं. भ्रष्टाचार के जड़ तक नही पहुंच पाते.

भ्रष्टाचार के खिलाफ इस से पहले भी आन्दोलन हुए हैं. १९७४ के आन्दोलन ने सैद्धांतिक भूमिका रखी. उस भूमिका से मतभेद हो सकते हैं लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ संपूर्ण क्रांती का नारा देकर समाज को संघटीत करने का वह गंभीर प्रयास था. पिछले १० वर्षों से इरोम शर्मिला मनीपूर में लागू अफस्पा कानून के खिलाफ अनशन पर बैठी हैं. सरकार उसकी न्यायपूर्ण मांगो का विचार करने के लिए भी तयार नही. उसके अनशन को आज तक किसी भी चैनल ने गंभीरता से नहीं लिया. शायद मनीपूर जैसे पुर्वोत्तर राज्य और जम्मू कश्मीर तथाकथित मुख्यधारा के भारत में नही हैं. सेझ जैसे देशविरोधी कानून के खिलाफ, जल, जंगल जमीन पूंजीपतीयों द्वारा हथियाने के खिलाफ चल रहे आदिवासी, किसानो, मछुआरों, अन्य पिछडों का संघर्ष भी तथाकथित मुख्यधारा के सिविल सोसायटी के ज़हन के बाहर हैं.

अन्ना हजारे की भूमिका को लेकर किसी भी तरह का सन्देह नहीं हैं. लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में अन्ना हजारे को हमेशा किसी न किसी राजनीतिक दल ने इस्तेमाल किया हैं. इस बार भी भ्रष्टाचार के मामले में कठघरे में खडी युपीए सरकार ने चतुराई से अपनी कमजोरीयों को लोकपाल के बहाने छिपाने की कोशिश की हैं. विडंबना यह हैं कि अन्ना के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में मनमोनह सिंह भी हैं और सोनिया गांधी भी ! लेकिन चार दिन चले इस अनशन ने अमिर खान की हाल ही में आई फिल्म ''पिपली लाईव'' की तीव्रता से याद दिलाई. उस फिल्म में जिस तरह से किसान नायक 'नथा' आत्महत्या करेगा के नही इस पर पुरे चॅनेलवाले धंदा करते है उसी तरह से अन्ना अनशन छोडेंगे के नहीं इस पर ICC वर्ल्ड कप और IPL 20-20 क्रिकेट के बीच के समय में टीआरपी बढाने के धंदे में चैनलवाले व्यस्त थे. ऐसे अनशन का बहुराष्ट्रीय कंपनी निर्मित बॉटलबंद नींबू पानी पिलवाकर छूटना बहुत कुछ बता देता हैं. समझनेवाले को इशारा काफी हैं.

❖❖❖❖❖❖

झारखंड धनबाद में अतिक्रमण के नाम लोगों को उजाडने का अभियान

राष्ट्रीय खेल, सडक चौडीकरण, सौंदर्यकरण के नाम पर शहरी गरीब, फूटफाट दुकानदारो को उजाडा गया. इसके बाद अब अतिक्रमण के नाम पर गरीबो का घर दुकान को उजाड दिया गया. लेकिन सरकारी जमीन पर बने बडे-बडे भवन बने हुए हैं. ट्रस्ट, कॉलेज के नाम पर सस्ते दरो में सरकारी जमीन (20 से 30 रुपये प्रति एकड़) दिया गया. लेकिन जरुरतमन्द गरीब जो बेघर हैं. उनके लिए सरकार की कोई योजना नहीं हैं. भारत कोकिंग कोल लि. सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जरेड़ा के साथ मिलकर पुर्नवास का काम कर रही हैं. करोड़ो रुपये केन्द्र सरकार ने दिया हैं लेकिन हाय कोर्ट से बी.सी.सी.एल. आवास पर कब्जा करने के खिलाफ आर्डर लिया हैं. लेकिन यह पूरी सरकारी या भूदान जमीन हैं जिसे कोल इंडिया की अंगीकृत इकाईयो ने हडप लिया हैं. छोटे किसानो की जमीन कब्जे में ले ली हैं. दो हजार से 20 हजार तक का प्रलोभन देकर लोगों की एकता तोड रहां हैं. झारखंड सरकार ने 10 वर्ष में पुर्नवास नीति नहीं बनाई हैं. झारखंड के राजस्व मंत्री का बयान हैं कि, BCCL जैसी कंपनीयो का जमीन का लीज 2003 में खत्म हो गया. फिर भी यहां के लोगों को बेघर किया जा रहा हैं. इस के खिलाफ संघटीत होकर आंदोलन करना होगा.

ता.क. - 27 अप्रैल को झारखंड पुलीसने BCCL कलोनी को खाली करने की कोशिश की फायरींग में ४ लोग मारे भी गए हैं और पुरे धनबाद शहर में कर्फ्यू लगाया गया. युवा भारत पुलीस दमन की तीव्र निंदा करता हैं. (यह रिपोर्ट धबाद के सामाजिक कार्यकर्ता डा. बी. श्रीवास्तव जी ने भेजा हैं)

❖❖❖❖❖❖

धनबाद में युवा भारत इकाई का गठन

दि. १७ अप्रैल को युवा भारत की बैठक शच्चरत भवन, पूटकी बाज़ार, धनबाद में हुई. यु.भा. सलाहकार समिती सदस्य तथा वरीष्ठ कार्यकर्ता रामचंद्र रमाणी जी प्रयास से हुई इस बैठक में धनबाद जिले के विभिन्न इलाको से ३५ युवा कार्यकर्ता उपस्थित थे. इस बैठक में झारखंड राज्य, धनबाद की समस्या को लेकर गंभीर चर्चा हुइ. धनबाद इलाके में चल रहे आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने का निर्णय इस बैठक में लिया गया. ७ सदस्यीय धनबाद जिला समिती का गठन किया गया. साथी कृष्ण प्रसाद महातो को सहमतीसे जिला संयोजक की जिम्मेदारी दी गई. इस बैठक को राष्ट्रीय संयोजक प्रदीप रॉय, कौशिक भारत, राष्ट्रीय समिती के सदस्य बिरेन्द्र और तपोती ने संबोधित किया.

युवा भारत की राष्ट्रीय समिती बैठक हावड़ा में संपन्न

दि. 5 एवं ६ मार्च, 2011 को युवा भारत की राष्ट्रीय समिती और सलाहकार समिती की बैठक 'कस्तुरबा भवन' मौरीग्राम, हावड़ा प. बंगाल में संपन्न हुई इस बैठक में यु.भा. के राष्ट्रीय संयोजक प्रदीप रॉय, कौशिक भारत, राजीव राय और शशी सोनवणे उपस्थित थे. साथी विनोद भाई और हरेन्द्र बैठक में पारिवारीक कारणो की वजह से उपस्थित नहीं हो पाए. राष्ट्रीय समिति सदस्य तपोति चॅटर्जी, अलपना बेरा, मनोज दास, सुशांत, शंतनु, सूनील चौधरी, मुक्ता सोनवणे, उद्धव धुमाले, वनराज शिन्दे उपस्थित थे. यु.भा. के सलाहाकार समिती सदस्य अशोक भारत और सुर्यदेवजी उपस्थित थे, इस के अलावा यु.भा.के समर्थ एवं विचार रोनेश रॉय, चंदना मित्रा, यु.भा. बंगाल के साथी इक्बाल, प्रसून दास, बिमन बिहारी कयाल, राजू दास, तरुण सामंता, विश्वजीत पाल, प्रेमानंद दास, अर्चना मंडल आदि साथी उपस्थित थे.

पहले दिन कुछ साथी ट्रेनो के विलंब के कारण देरी से पहुंचे. बैठक दोपहर के बाद शुरु हुई. नव उदारमतवादी नीतियों के 20 साल पुरे होना और यु.भा. की स्थापना को 10 साल पुरे होना इस संदर्भ साथीयो ने गंभीर चर्चा की. साथी शशी, अशोक भारत, प्रदीप, एवं सुर्यदेवजी ने 20 वी सदी के अंत के समय की राजनीतिक स्थिती का और उसके प्रतिक्रिया के रुप में विकल्प खडा करने की कोशिश के रुप में युवा भारत के प्रवास को रखा. साथी अशोक भारत ने इस बात पर जोर दिया कि संगठन ने देश में नई संभावना पैदा जरुर की लेकिन उसकी जो गतिशिलता अपेक्षित हैं उतनी गतिशिलता दिख नहीं रहीं. इस चर्चा को आगे बढाते हुए बंगाल के विचारक रोनेश रॉय ने कहा कि वैश्विकरण के दौर में पुंजीवाद नई ऊंचाई पर चला गया हैं वर्ग संघर्ष, सामाजिक न्याय, पर्यावरण और सार्वभौमत्व के सवालों को एकसाथ देखना होगा. पहले मध्यम वर्ग नेतृत्व करता था और पार्टी dictate करती थी लेकिन अब लोग खुद आगे बढ़ रहे हैं. यह महत्वपूर्ण बदलाव हैं. इस चर्चा में साथी प्रदीप ने 10 मुद्दे रखे - 1. महामंदी के बाद पूंजीवाद ने जो कल्याणकारी राज्य की भूमिका ली थी उसे समाजवाद के प्रयोग ढहने के बाद छोड दिया. 2. एकाधिकार पूंजी का एशिया, अफ्रिका, लॅटीन अमरिका में विदेशी निवेश के रुप में फैलना, 3. भारत में एकाधिकार पूंजी का आय.टी, रीयल इस्टेट, शेयर मार्केट जैसे क्षेत्रो में हस्तक्षेप करना, 4. उदारीकरण, नीजीकरण, वैश्वीकरण के नाम पर संरचनात्मक बदलाव लाने की प्रक्रिया 1991 के बाद शुरु होना, 5. तीसरी दुनिया के सभी देशों में जल, जंगल, जमीन एवं मानवी श्रम का बेहिसाब शोषण की प्रक्रिया चलना, 6. कोई और विकल्प नहीं होने की घोषणा मिडीया द्वारा बार बार करना, 7. जैविक तंत्रविज्ञान से कृषी क्षेत्र पर एकाधिकार पूंजी का कब्जा जमाने की कोशिश, 8. मजदूर वर्ग पर पूंजी द्वारा हमले तेज होना. 9. अमरिका के नेतृत्व में एक धृवी दुनिया को बढावा देना.

इन मुद्दो के अलावा अन्य कई सारे आयाम पर भी साथीयो ने चर्चा की. सभी साथीयों की राय से नवउदारमतवादी नीति के 20 वर्ष और युवा भारत के स्थापना के 10 वर्ष इस विषय पर यु.भा. का राष्ट्रीय शिबीर भागलपूर में लेने का निर्णय हुआ.

संगठनात्मक चर्चा में साथीयो ने रिपोर्ट रखी - **बंगाल** : डॉ. कोटनीस पर पर्चा निकाला गया और 11 दिसंबर, 2010 को कार्यक्रम लिया गया. बिहाला और बावडीया पुस्तक प्रदर्शन में हिस्सा लिया. पॉस्का, लालगड़, बिनायक सेन के मुद्दे पर पोस्टर कॅम्पेन चलाया. जीएम राईस के सवाल पर बंगाल में आंदोलन किया गया. नेताजी सुभाषचंद्र बोस जयंती के दिन हावड़ा में यु.भा की तरफ से जुलूस कार्यक्रम किया गया. **बिहार** में भागलपूर विश्वविद्यालय में वी.सी. की नियुक्ती में भ्रष्टाचार के मामले पर और गांधी विचार विभाग के डा. विजय के निलंबन के विषय पर यु.भा अन्य विद्यार्थी संगठनों को जोडकर आन्दोलन किया. क्रेडीट सोसायटी की जिला स्तरीय समिती में हस्तक्षेप कर किसानो को सस्ता खाद मिलने के लिए यु.भा. ने प्रयास किया. **महाराष्ट्र** - पुणे में 17 फरवरी को दलित, आदिवासी obc विद्यार्थीयो के फ्रिशीप के सवाल पर समाज कल्याण कार्यालय पर मोर्चा निकाला. आनेवाले दिनो में पुरे राज्य में इस विषय पर आन्दोलन की तयारी चल रही हैं.

संगठनात्मक चर्चा मे बंगाल के राज्य स्तर के संगठन में आनेवाली कठीनाईयो और उपायों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई.

इस बैठक में लिए गए निर्णय :

1. संगठन के विस्तार के लिए यु.भा. के पिछले 10 वर्षो के प्रवास को लेकर पुस्तिका प्रकाशित करने का निर्णय लिया. यु.भा. के शिबीर में इस पुस्तिका का ड्राफ़्ट प्रदीप रॉय, शशी और अशोक भारत तयार करके रखेंगे.
2. युवा भारत समाचार नियमित रुप से प्रकाशित करने के लिए शशी, राजीव राय और इक्बाल इन तीन साथीयों की मिलकर संपादक मंडल बनाने का निर्णय लिया गया.
3. अगला राष्ट्रीय सम्मेलन महाराष्ट्र में लेने का निर्णय लिया गया.
4. भागलपूर में राष्ट्रीय शिविर जून 5-6-7 मई, 2011 को होगा.

अगली राष्ट्रीय समिती की बैठक 8 जून, 2011 को भागलपूर में होगी.

❖❖❖❖❖❖

पॉस्को विरोधी संघर्ष तेज करने की घोषणा

उड़ीसा के जगदीशपूर जिले के बालीतूठ में दि. १३ मार्च के पॉस्को विरोधी विशाल जनसभा हुई. पॉस्को प्रतिरोध संग्राम समिती द्वारा आयोजित इस सभा में नुआगांव, डिकिया आदि गांवो से सेकड़ो, महिला पुरुष ने सहभग लिया. आन्दोलन के नेता अभय साहू ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि, उड़िसा सरकार और केन्द्र सरकार संविधान और कानून को तोडकर पॉस्को प्रकल्प लोगो पर थोपने की कोशिश कर रही हैं. इस सभा में छत्तीसगढ विस्थापन विरोधी मंच, बस्ती सुरक्षा मंच, उड़िसा आदिवासी अधिकार अभियान, वनवासी सुरक्षा परिषद, राजधानी उन्नयन मंच, पत्रकार रविदास रॉय, पर्यावरणवादी प्रफूल्ल सामंत्रा ने सभा को संबोधित किया. CPI, CPI(M), फॉरवर्ड ब्लॉक, राजद, SUCI, CPI(ML)-ND, CPI(ML) Red Star पार्टीयो ने इस आन्दोलन को समर्थन दिया. युवा भारत शुरु से इस आन्दोलन को सक्रिय समर्थन देता आया हैं. आगे की लडाई में भी यु.भा. ठोस भूमिका लेगा यह बात यु.भा. के राष्ट्रीय संयोजक प्रदीप रॉय ने अपने भाषण में रखी.

पृ १ से

गोलीया दाग रही हैं - जैतापूर, महाराष्ट्र में १८ अप्रैल को पुलीस फायरींग में एक आंदोलनकर्ता तबरेज सोयेकर मारा गया. इस के पिछे की राजनीति को समझना होगा.

पर्यावरण के बिघडते संतुलन और उसके लिए जिम्मेदार कार्बन आधारीत ऊर्जा स्त्रोत के विकल्प में अन्य ऊर्जा स्त्रोतों को लेकर पिछले कुछ वर्षों में काफी गंभीर बहस चली हैं. कई सारे प्रयोग भी चल रहे हैं. वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोत के रुप में परमाणू ऊर्जा को पर्यावरण की दृष्टी से स्वच्छ एवं ग्रीन एनर्जी के रुप में पिछले कुछ दशको से बडे जोर-शोर से प्रचारीत किया जा रहा हैं. लेकिन पुरी दुनिया में जितने भी परमाणू संयंत्र (न्युक्लीयर रियाक्टर) लगे हुए हैं वे दरअसल अपनेआप में परमाणू बम हैं. परमाणू संयंत्र एक बार लग जाने के बाद उसे बंद करना मुश्किल होता है. ऐसे संयंत्र बंद भी किए जाए तो उन्हें अनंत काल तक संभालना पडता हैं. परमाणू संयंत्र को खडा करना और उसे संभालना और उस से उत्पन्न परमाणू कचरे को अनंत काल तक संभालने के लिए बहुत अधिक पुंजी निवेश की जरुरत होती हैं. इतना करने के बाद भी रेडीयेशन नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती. परमाणू संयंत्र के ढांचे में दोष हो या कोई मानवी भूल या प्राकृतिक आपदा से परमाणू संयंत्र को नुकसान हो जाए तो उस संयंत्र को बंद करना या नियंत्रीत रखना मुश्किल होता हैं. यह अनुभव बार बार आ रहा हैं. परमाणू ऊर्जा के समर्थकों का दावा हैं कि ऐसे हादसे होने के प्रमाण बहुत कम हैं. लेकिन जो हादसे हुए उनका दु:प्रभाव हजारो वर्ष रहेगा. १९७९ में अमरिका के थ्री माइल आयलंड में और २६ अप्रैल १९८६ को भूतपुर्व सोविएत युनियन के चेर्नोबील में भयंकर हादसे हुए. रशियन अकादमी ऑफ मेडिकल सायन्स के अनुमान के अनुसर चेर्नोबिल के हादसे से अब तक २ लाख १२ हजार लोग मर चुके हैं और लाखो लोग अपनी मौत का इंतजार कर रहे है. यह सिलसिला सैकडो वर्ष चलने का डर हैं. आज भी चेर्नोबिल से विकिरण का संकट जारी है. इससे फुकुशिमा हादसे के दु:प्रभावों की व्यापकता का अंदाजा लगाया जा सकता हैं.

ऐसा होते हुए भी भारत सरकार परमाणू ऊर्जा को लेकर उत्साहीत हैं. मनमोहन सिंह सरकार २०५० तक कुल बिजली निर्मिती का २५ % हिस्सा परमाणू ऊर्जा से करना चाहती हैं. इसके लिए देश का सार्वभौमत्व को खतरे में डालने वाला परमाणू करार अमरिका, फ्रान्स जैसे देशो के साथ किया. इस के पिछे परमाणू लॉबी काम कर रही हैं. पुरी दुनिया खास तौर पर अमरिका और युरोप आर्थिक मंदी से गुजर रही हैं. ऐसे समय में अरबों रुपयों की लागतवाले पर परमाणू बिजली निर्मिती केन्द्र विकसीत करने के ठेके जी.ई इलेक्ट्रानीक्स, अरेवा, रोसाटम आदि कंपनीयो को मिलना उन देशों की आर्थिक स्थिती को भी मजबूत करने में मदत करता है और भारत जैसे देशों पर अप्रत्यक्ष अंकुश भी लगा देता हैं. ऊर्जा संबंधी चर्चा समाज की जरुरते, पर्यावरण के संतुलन इस संदर्भ में नही होती हैं. पूंजीवादी मुनाफे के सामने यह मुद्दे गौण साबित होते हैं. पुरी दुनिया में खनिज संपत्ती - तेल, कोयला आधारीत कार्बन लॉबी और परमाणू लॉबी इन के बीच ऊर्जा क्षेत्र का अर्थकारण चलता हैं और दोनो लॉबी दुनिया के बडे पूंजीपती वर्गो के कब्जे में हैं. इसके अलावा जो अपारंपारीक ऊर्जा स्त्रोत जैसे सौर, पवन ऊर्जा है - उसे विकसीत करने का प्रयास इन आर्थिक हितसंबंधो के कारण नहीं किया जाता हैं. जो भी थोडे बहुत प्रयास भारत में हमे दीख रहे हैं वे अपनेआप में बहुत बडे घोटाले हैं. पवन ऊर्जा के नाम पर यहां की जमीन हथियाने का षडयंत्र खुले आम चल रहा हैं और इस काम के लिए ऊपर से सरकारी सबसिडी भी ली जाती हैं!

असल में ऊर्जा की जरुरत पर ठीक से पुर्नविचार होने की जरुरत हैं. पुरे देश में एक ओर जहा देहाती इलाके अंधेरे में हैं, कृषी के लिए पर्याप्त बिजली नहीं होने के कारण किसानी अधिक संकट में हैं वहीं दुसरी ओर बडे महानगरों में बिजली की अनावश्यक चमक धमक हैं. तीन सदस्य वाले मुकेश अंबानी परिवार का महिने का बिजली बील ६६ हजार रुपए हैं. आज बिजली के वितरण का सोशल ऑडीट करने की जरुरत हैं. मुनाफा केन्द्रीत नहीं बल्कि समाज केंन्द्रीत दृष्टीकोन से पर्यावरण की रक्षा करनेवाले वैकल्पीक ऊर्जा स्त्रोतों को विकसीत करने की जरुरत हैं. पूंजीवाद यह नहीं करने देगा. इसलिए हमारा संघर्ष अधिक तीव्र करना होगा. इसके सिवा और कोई विकल्प नहीं हैं.

❖❖❖❖❖❖

नौजवानों का नशाबाजी के खिलाफ लढना चाहिए – ह.भ.प. बंडा तात्या महाराज कराडकर

महराष्ट्र के मराठवाडा मे बुलढाणा जिले के चोरपांगरा गांव में युवा भारत के युनिटने महिलाओं के सहयोग से गांव को शराब मुक्त किया और गांव के दलित पिछडो के लिए रचनात्मक कार्य किया है. इस कार्य को पूरे जिले में फैलाने के उद्देश्य से यु.भा. ने ११ फरवरी को चोरपांगरा गांव में जनसभा का आयोजन किया. पुरे जिले से आए चार हजार लोगों को संबोधित करने के लिए आए डाऊ विरोधी आन्दोलन के नेता तथा वारकारी सम्प्रदाय के वरीष्ठ किर्तनकार ह.भ.प. बंडा तात्या महाराज कराडकर ने साथीयों के प्रयास का अभिनंदन करते हुए उनके इस प्रयास को हमेशा सक्रिय समर्थन देने का आश्वासन दिया. सेझ विरोधी, डाऊ विरोधी आंदोलन के नेता तथा यु.भा.के एक संस्थापक कॉ. विलास सोनवणे जी ने सत्ता, धन जैसे व्यसन से समाज को मुक्त करने का नौजवानो को आवाहन किया.

युवा भारत आगामी कार्यक्रम

विदर्भ विभागीय शिवीर, दि. 6-7-8 मई, 2011, परसोडी, बूटीबोरी, नागपूर, महाराष्ट्र
पश्चिम महाराष्ट्र विभागीय शिवीर दि. 14-15 मर्ठ, 2011, पुणे, महाराष्ट्र
संपर्क: सुनील चौधरी 9373126450, उद्धव धुमाले 9921358234, वनराज शिन्दे 9921494696

डा. अरुण कुमार अरुण, मुद्रक, प्रकाशक और स्वामी द्वारा मर्करी प्रिंटर्स, 602, गली जुतेवाली, चूड़ीवालान, दिल्ली 06 से मुद्रित एवं 167ए/जी.एच-2, पश्चिम विहार, नई दिल्ली - 63 से प्रकाशित. संपादक: डा. अरुण कुमार अरुण फोन: 011-25272799 **RNI-DELHIN/2003/9926**